प्रेषक,

एच0पी0 सिंह, संयुक्त सचिव, उ०प्र0 शासन।

2578/c/S

सेवा में,

1. निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ। समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एंव गरीबी उन्मूलन कार्यकम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक २ 🕂 अप्रैल, 2015

विषयः रिट पिटीशन (सी) सं0-494/2012, जस्टिस के0 एस0 पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (कोर्ट 6, आइटम 301) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग—1 (नियोजन विभाग) द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या—3/2015/17एम(4)/35—310—1/2009—12टी0सी0—1 दिनांक 31 मार्च, 2015 एवं उसके साथ संलग्न महा—सॉलिसिटर भारत के पत्र दिनांक 16.03.2015, जो प्रश्नगत याचिका में आधार निर्गमन की वैधता से सम्बन्धित दिनांक 16.03.2015 को सुनवाई के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2013 को पारित आदेश का समस्त अथारिटी द्वारा अनुपालन के दिये गये निर्देश से सम्बन्धित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। आदेश का क्रियात्मक अंश अधोलिखित है:—

"In the meanwhile, no person should suffer for not getting the Adhaar card inspite of the fact that some authority had issued a circular making it mandatory and when any person applies to get the Adhaar card voluntarily, it may be checked whether that person is intitled for it under the law and it should not be given to any illegal immigrant."

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2015 एवं उसमें उल्लिखित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2013 का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदाय, (एच०पी० सिंह) संयुक्त सचिव।

संख्या-1014(1) / 69-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश। संलग्नकः यथोक्त।

AD 28/4/15

APO(31(Gr)

(एच0पी0 सिंह) संयुक्त सचिव।

2014/15 2014/15 05:10 PM

1014/69-1-2015

लखन्जःदिनांकः 31 मार्च, 2015

## महत्वपूर्ण/मा० सर्वोच्च न्यायालय निर्देश संख्या:3/2015/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12टी०सी०-1

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

स्वन्य सचिव सम्बद्धाः सम्बद्धाः शासन। समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

राज्य योजना आयोग-1 (नियोजन विभाग)

द्वितीय तल, योजना भवन

विषयः रिट पिटीशन (सी) सं० ४९४/२०१२-जस्टिस के०एस० पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (कोर्ट 6, आइटम 301)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महा-साँतिसिटर भारत के पत्र दिनांक 16-03-2015 (प्रतिलिपि संलग्न) जो प्रश्नगत याचिका में आधार निर्गमन की वैधता से सम्बन्धित दिनांक 16-03-2015 को सुनवाई के दौरान मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 23-09-2013 के पारित आदेश का समस्त अँथारिटी द्वारा अनुपालन के द्रिये गये निर्देश से सम्बन्धित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आदेश का क्रियोत्मक अंश अधोवत् है:-

In the meanwhile, no person should suffer for not getting the Adhaar card inspite of the fact that some authority had issued a circular making it mandatory and when any person applies to get the Adhaar card voluntarily, it may be checked whether that person is entitled for it under the law and it should not be given to any illegal immigrant."

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहनें का निदेश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-09-2013 का कड़ाई से अक्षरशः

अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

रिपाठांड रेट्रीफिर असे राजती के जरता केरी

प्रमुख सचिव

Worklath

नगर विकार जन्महर्ग विकार

रंजीत कुमार नहा-संलिखिटर भारत

RANJIT KUMAR Solicitor General of India



Office/Chapther: 27. Law Officers' Chambers. Supreme Court of India Tel.: (+91) (11) 23381636, Fax: 23070238

E-mail: sgofficerk@gmail.com

16<sup>th</sup> March 2015

Sub: WP (C) No.494/2012 - Justice K.S. Puttaswamy (Retd) v. UOI [Court 6, Item 301]

Dear

The abovementioned batch of matters relating to the validity of the issuance of Adhaar cards which has to be heard by a Bench of three Hon'ble Judges was taken for hearing on 16.03.2015. It has been directed by order passed today that it be heard in the second week of July 2015.

In the meantime, the Court has directed today that the order that was passed by the Court on 23.09.2013 should be adhered to by all authorities i.e., the Union of India, all the States and all other authorities within the meaning of the Constitution of India. The operative portion of the order dated 23.09.21013 is quoted hereinbelow for your ready reference:-

"In the meanwhile, no person should suffer for not getting the Adhaar card inspite of the fact that some authority had issued a circular making it mandatory and when any person applies to get the Adhaar Card voluntarily, it may be checked whether that person is entitled for it under the law and it should not be given to any illegal immigrant."

This was necessitated on account of the fact that some of the Petitioners brought it to the notice of the Court that some of the States/authorities were violating the said order and were insisting that Adhaar cards would be necessary for availing of some of the Government services or benefits.

Since it was observed by the Hon'ble Court that I should convey the strict compliance/adherence of the order dated 23.09.2013. Lam writing this letter to you so that this order is fully adhered to. You are requested to please make sure of adherence of this order.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-(Ranjit Kumar)

Shri Ajit Seth, Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi



## Copy to:-

- 1. Shri L.C. Goyal, Home Secretary, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
- Shri Rajiv Mehrishi, Finance Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
- 3. Shri Saurabh Chandra, Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Shastri Bhavan, New Delhi
- Shri Rajeev Kher, Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhavan, New Delhi
- Ms. Sindhushree Khullar, Secretary, Planning Commission, Yojana Bhavan, Parliament Street, New Delhi.
- Shri V.S. Madan, Director General & Mission Director, Unique Identification Authority of India, Government of India, 3rd Floor, Tower II, Jeevan Bharati Building, Connaught Circus, New Delhi – 110001
- 7. Chief Secretaries of all the States/UTs.